

गोण्ड जनजाति में शिक्षा का बदलता प्रतिमान

¹डॉ कमलेश पाल

सारांश

विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे एक आकर्षक गुलदस्ता है, 'हमारा भारत' और भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। मध्य प्रदेश जिसे प्रकृति ने राष्ट्र^a की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौन्दर्य और मनमोहक सुगन्ध चारों ओर फैल रहा है। यहां के जनपदों की आबोहवा में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोक समूहों और जनजाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रूप से फूटती रहती है। यहां का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनन्द रस घोलकर स्मृति के रूप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुंग-उत्तुंग, शैल-शिखर, विन्ध्य-सतपुड़ा, मैकाल-कैमूर की उपत्यिकाओं के अंतर से गुंजते अनेक पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिंध, चम्बल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती आदि सर-सरिताओं के उद्गम मिलन से फूटती सहस्र धारारें यहां के जीवन को आप्लावित ही नहीं बल्कि परितृप्त भी करती हैं।

मूल शब्द: गोण्ड जनजाति, शिक्षा, आदिवासी, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास ।

Corresponding Author

¹सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जौनपुर
email: kamalesh.alld@gmail.com

प्रस्तावना

1 नवम्बर, 1956 को गठन हुए मध्यप्रदेश में भोपाल को उसकी राजधानी बनाया गया। वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश 1 नवम्बर, सन् 2000 को अस्तित्व में तब आया, जब छत्तीसगढ़ राज्य का बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश राज्य देश के मध्य में स्थित है, इसी कारण मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। 1 नवम्बर, 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ से अलग होने के पश्चात् इसकी

सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। राज्य का क्षेत्रफल तीन लाख, आठ हजार, दो सौ, बावन (3,08,252) वर्ग कि० मी० है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7,26,26,806 है।

मध्य प्रदेश विभिन्न जनजाति के लोगों से अच्छादित है। विभिन्न आदिवासी समुदायों के अन्तर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कि न सिर्फ उनके आनुवांशिकी जीवन-शैली और सांस्कृतिक परम्पराओं पर आधारित है। बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक संरचना, धार्मिक विश्वास, भाषा और बोली पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समूह विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग रहे हैं। जिसकी वजह से विभिन्न भाषायी एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सुरक्षित रही है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या (2011) 1,53,16,784 है। जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 18.46 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 46 चिन्हित अनुसूचित जनजातियां हैं जिसमें से तीन को प्रदेश में विशेष प्रांरिक आदिवासी समूह माना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी समूह गोंड, बैगा, भील, कोरकू, मारिया, हलवा, कोल, भारिया और सहरिया हैं। धार, झाबुआ और मंडला जिलों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनजातियां रहती हैं। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी और शहडोल जिलों में 30 से 50 प्रतिशत तक जनजातियां रहती हैं।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंड जनजाति की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीनकाल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी। जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था।

गोंड शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति के साथ इनकी जीवन-शैली पहनावा और आराधना की पद्धतियों को आधार बनाकर इनकी उत्पत्ति के बारे में अद्यतन समाजशास्त्रियों द्वारा मंथन एवं विचार किया जाता रहा है। कुछ का दृष्टिकोण इनके पहनावे के आधार पर है तो कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता इनके प्रवास के मिलते क्रमिक विकास के आधार पर है। इतिहास का प्रमुख आधार साहित्य हुआ करता है और भारतीय साहित्य मिथकों से भरा पड़ा है। पुराणों में इतिहास का लेखन ही मिथकीय शैली में हुआ है। भारतीय जनजातियों के सन्दर्भ में अनेक मिथक या पुराकथायें प्रचलित हैं। गोंड जनजातियों की भी उत्पत्ति संबंधी मिथकों की एक श्रृंखला है। गोंड स्वयं को गोंड नहीं अपितु 'कोयतोर' कहते हैं और गोंडों की अनेक उपजातियां हैं। गोंड शब्द

शजळ्ळक्श् (कोंड) का हिन्दी रूपान्तर है जिनके लिए 'कोयतोर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'हिसलप' के अनुसार-गोंड या 'गुण्ड' शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है।

छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले को मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के बहुमुखी नगरी के रूप में देखा और जाना जा सकता है यहाँ पर मूलरूप से तो आदिवासी संस्कृति के परिवेश में बसी हुई इस समाज की सामाजिक धरोहर नजर आती है किन्तु कोल इंडिया के प्रमुख श्रोत के रूप में उत्पन्न कोल इंडिया के संसाधनों में सम्पूर्ण भारत की संस्कृति के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों के बीच भी यह आदिवासी समाज की समस्याएँ एवं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा एवं उसकी पद्धति, इनके वैवाहिक जीवन, इनकी भाषा, शिक्षा के स्तर आदि को देखकर इसके पिछड़ेपन के कारण इसको को अलग से ही पहचाना जा सकता है। व्यवसाय में बर्तन बनाना, चटाई टोकरी एवं सूपा के साथ आदिवासियों की जीवन-शैली लिए इस क्षेत्र का अधिकांश आदिवासी आज भी अपने उपयोग के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुयें जंगलों से प्राप्त करता है। मैंने इस शोध यात्रा के दौरान यहाँ की साप्ताहिक बाजारों में सुदूर ग्रामीणों से आने वाले आदिवासियों को वनों से खोदकर लाये विभिन्न प्रकार के कांदा, छिन्दो कांदा, पाजर कांदा, चांदी कांदा आदि को सुखाकर एवं भूनकर खाते देखा। वन सिंघाड़ा एवं वन अदरक का औसत के अनुरूप उपयोग करते देखा। इन आदिवासियों के सब्जियों का श्रोत भी वन ही दिखाई देता है। महुआ, गोंद, चिरौंजी, मकोई, आंवला, गूलर, इमली आदि को भोजन के रूप में अपनाने वाले अधिकांश आदिवासियों का सामाजिक-आर्थिक जीवन महुआ पर केन्द्रित है। खनिज उत्खनन में मजदूरी करना ही इनकी सर्वोच्च उपलब्धि दिखाई देती हैं। संयोग से आदिवासी क्षेत्र वन सम्पदा की भाँति खनिज सम्पदा में भी सम्पन्न है और छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले में कोयले का अकूत भंडार है। इस कारण से आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी बदला हुआ प्रभाव दिखाई देता है। अध्ययन हेतु चयनित तहसील आमला एवं जुन्नारदेव दोनों स्थानों पर शासकीय महाविद्यालय स्थापित है। यद्यपि कि इन महाविद्यालयों के अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को इस क्षेत्र का आदिवासी समाज न तो अपेक्षाकृत प्रभावित कर पाया है और न ही लाभान्वित हो पाया है। इस अनुशीलन के दौरान मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाने मात्र से जुन्नारदेव एवं आमला के आदिवासियों में साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। आदिवासी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान मुझे देखने को मिली कि प्रत्येक बालक-बालिका एक मुँह के साथ दो हाथ लेकर आता है और अपने परिवार का वह कार्यकर्ता बना रहता है परिणामतः वह कमाने लगता है। फलतः उसे या तो स्कूल भेजा नहीं जाता अथवा वह केवल मध्याह्न भोजन मात्र के लिए अल्पकालिक एवं नियमित होता है। आदिवासी

बाहुल्य क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान मैंने पाया कि माध्यमिक विद्यालयों की उम्र तक वह कमाऊँ पूत समझा जाने लगता है। तमाम शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बाद भी आदिवासियों में साक्षरता बहुत कम है। यद्यपि कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सामान्य कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप इनकी साक्षरता में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। परन्तु यह वृद्धि आदिवासी जनसंख्या को सामान्य जनसंख्या के समकक्ष नहीं ला सकती है। जहाँ तक स्त्री और पुरुष साक्षरता की दरों का प्रश्न है, शासकीय आँकड़ें चाहे कुछ भी बताते हों पर मुझे तो साक्षर पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 5 और 1 ही नजर आता है। जुन्नारदेव का आदिवासी समाज भले ही कोल इण्डिया के सम्पर्क में हो लेकिन वह अपनी भाषायी संस्कृति को संभाले हुये है। बहु भाषा-भाषी क्षेत्र होने के बावजूद भी आदिवासी समुदाय की वेश-भूषा, रीति-रिवाज, खान-पान, बोली-भाषा प्रभावित हो रही है किन्तु ये अपनी बोलियों एवं भाषाओं को अभी भी अपनाते नजर आते हैं। आदिवासी अभी भी अपनी बोलियाँ संजोए हैं इसमें संदेह नहीं है। अतः विकास की योजनायें बनाते समय शासन को इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनाने में आदिवासी शिक्षा की तुलना में अब भी पीछे हैं। आज भी स्वास्थ्य संबंधी उनके विचार, अंधविश्वास एवं धर्म के नियमों से नियंत्रित होते हैं। केवल अस्वस्थता की चरम सीमा आने पर ही वह अपने धार्मिक आदेशों की सीमा लांघने के लिए विवश होते हैं और अस्पताल एवं डाक्टर के पास जाते हैं।

मैंने इस शोध यात्रा के दौरान परिचर्चा के बाद यह निष्कर्ष पाया कि आदिवासियों में कोई बीमारी या प्रकोप हो तो उसके वे केवल दो ही कारण मानते हैं। एक ग्रामी देवी-देवता का क्रुद्ध होना दूसरा जादू-टोना एवं भूत-टोटका। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में अस्वस्थता के इन दोनों कारणों को दूर करने के लिए किये गये उपायों का अनुशीलन करने पर पाया कि गाँव में अलग-अलग विशेषज्ञ नियत होते हैं। पौधों की जड़ से लेकर पत्ती तक की उपयोगिता का ज्ञान इन्हें होता है। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह आया कि इस शोध कार्य के दौरान आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सहारे स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाले की मृत्यु पर ये विशेषज्ञ आधुनिक पद्धतियों की विफलता को उजागर करते हुए अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है। इस तरह वह अपनी अनन्त कालीन विश्वास और अपने रूढ़िवादी विचार को तोड़ नहीं पाता है। अगर आता भी है तो वह सरकारी तंत्र की लम्बी प्रक्रिया से बच निकलने के लिए निजी डाक्टरों के पास जाता है। शासकीय चिकित्सालय हो जाने के बाद भी इस तरह की अवरोधक प्रक्रिया निश्चित ही अलग शोध का विषय है।

मध्य प्रदेश 'जनजाति' बाहुल्य प्रदेश है जिसमें भारत की अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश में लगभग 1,53,16,784 अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 18.46 प्रतिशत है। जिसमें गोंड जनजाति की कुल जनसंख्या 43,57,918 है, जिसमें 21,90,962 पुरुष तथा 21,66,956 महिलाएं हैं। इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल जनसंख्या 6,41,421 है। जिसमें से गोंड जनजाति की जनसंख्या 5,30,485 है जिसमें 2,66,259 पुरुष तथा 2,64,226 महिलाएं हैं।

छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले के रूप में जाना जाता है। जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किमी⁰ है और प्रदेश के 3.85 प्रतिशत क्षेत्रफल का हिस्सा है। छिंदवाड़ा जिले का गठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ था। यह सतपुड़ा श्रृंखला पर्वत क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। यह 21.28 से 22.49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 78.40 से 79.24 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है। यह जिला दक्षिण में महाराष्ट्र के नागपुर जिले से घिरा है, उत्तर में होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले से, पश्चिम में बैतूल से और पूर्व में सिवनी जिले से घिरा है। जिले के अंदर समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की ऊंचाई 862 से 1200 मी⁰ है। छिंदवाड़ा जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 130 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई लगभग 136 किलोमीटर है। जिले का नाम उसके मुख्यालय नगर से है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि 'छीन्द' एवं खजूर के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस जिले का नाम छिंदवाड़ा रखा गया है। सम्पूर्ण जिला चतुर्भुज के आकार में भारत की हृदयस्थली मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित है। सम्पूर्ण जिले का विस्तार जबलपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर मैदान से लेकर उत्तर में नर्मदा घाटी तक है। जिले का 70 प्रतिशत भाग गोदावरी के कछार में आता है जिसकी प्रमुख सहायक नदियां कन्हान, पेंच एवं वर्धा है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तथा जिले का 30 प्रतिशत भाग नर्मदा के कछार में आता है जिसकी प्रमुख सहायक नदियां शक्कर, सीता रेखा, देनवा, दूधी एवं तवा है जो उत्तर की ओर बहती हुई नर्मदा से मिलती है। छिंदवाड़ा जिला 12 तहसीलों में विभक्त है-जिसमें छिंदवाड़ा, हरई, मोहखेड़ परासिया, जुन्नारदेव, उमरेठ, तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, सौंसर और पाढुर्ना है।

सारणी 01: वर्तमान में शाला होने की स्थिति।

क्र.	शाला की स्थिति	पुरुष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति

1	हॉ	124	82.67	122	81.33	246	82.00
2	नहीं	26	17.33	28	18.67	54	18.00
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 01 में जनजातीय क्षेत्रों में शाला होने की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुरुष उत्तरदाताओं में 82.67 प्रतिशत ने माना कि उनके यहां शाला है जबकि 17.33 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उनके यहां शाला की व्यवस्था अभी भी नहीं है। इसी प्रकार महिला उत्तरदाताओं में 81.33 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उनके यहां शाला की व्यवस्था है जबकि 18.67 ने स्वीकार किया कि उनके यहां अभी भी शाला की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार कुल महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं में से 82.00 प्रतिशत के यहां शाला की व्यवस्था है जबकि मात्र 18.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां शाला की व्यवस्था नहीं है।

अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्रों में भी शिक्षा की अनिवार्यता और शासकीय नीतियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परिणामस्वरूप इनमें शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। जहां इनकी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। अब वे भी शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं और बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील नजर आती हैं।

सारणी 02: यदि हॉ तो शाला का स्वरूप

क्र.	शाला का प्रारूप	पुरुष	महिला	कुल			
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	शासकीय	112	90.32	110	90.16	222	90.24
2	प्राइवेट	12	9.68	12	9.84	24	9.76
3	ईसाई मिशनरी	00	00	00	0.00	00	00.00
	योग	124	100.00	122	100.00	246	100.00

सारणी क्र० 02 में शाला के स्वरूप का अध्ययन किया गया है। जिसमें कुल उत्तरदाताओं में से 90.24 प्रति० ने शासकीय शाला की बात कही। जबकि 9.76 प्रति० ने निजी शाला के होने की बात कही।

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शासकीय योजनाओं से स्थापित शालाएं जनजातीय क्षेत्रों में अब स्थापित हो चुकी हैं जिसका लाभ जनजातियों को मिलने लगा है। वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में भी बिजली, सड़क एवं पानी की उचित व्यवस्था होने से अब वहां भी शाला आदि की व्यवस्था हो गयी है। पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से इनको भी शासकीय सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है। जिससे इनकी दिनचर्या एवं महत्वाकांक्षाएं बदलने लगी हैं।

सारणी 03: शाला में शिक्षकों की उपस्थिति की स्थिति।

क्र.	विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति	पुरुष	महिला	कुल			
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	110	88.71	110	90.16	220	89.43
2	नहीं	14	11.29	12	9.84	26	10.57
	योग	124	100.00	122	100.00	246	100.00

सारणी क्र० 03 में शाला में शिक्षकों की उपस्थिति का अध्ययन किया गया है जिसमें 11.29 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता इस बात से इन्कार करते हैं कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति रहती है। इसी प्रकार महिला उत्तरदाताओं में 90.16 उत्तरदाता का कहना है कि शाला में शिक्षक उपस्थित रहते हैं। जबकि मात्र 10.57 प्रतिशत महिला उत्तरदाता कहती हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति नहीं रहती है।

अतः इस आधार पर यह कह सकते हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति काफी ज्यादा रहती है और शासकीय शिक्षक समय से विद्यालय आते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इतना अधिक शिक्षकों की उपस्थिति पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही संभव हो पायी है। इनकी सक्रियता के कारण शिक्षक भी शिकायत के डर से समय से विद्यालयों में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

सारणी 04 : बालिका शिक्षा के प्रति लोगों की सोच

क्र.	बालिका शिक्षा के प्रति राय	पुरुष	महिला	कुल			
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	सकारात्मक	142	94.67	146	97.33	288	96.00
2	नकारात्मक	08	5.33	04	2.67	12	4.00
3	तटस्थ	00	00.00	00	00.00	00	00.00
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र० 04 में बालिका शिक्षा के प्रति उत्तरदाताओं की सोच को जानने का प्रयास किया गया है जिसमें पुरुष उत्तरदाताओं में 94.67 प्रतिशत लोग सकारात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं जबकि 5.33 प्रतिशत नकारात्मक विचार रखते हैं। इसी प्रकार महिला उत्तरदाताओं में 97.33 प्रतिशत सकारात्मक विचार प्रस्तुत करती हैं और मात्र 2.67 प्रतिशत महिला उत्तरदाता इस विषय पर नकारात्मक विचार व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार कुल पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं में से 96.00 प्रतिशत बालिका शिक्षा के प्रतिशत सकारात्मक विचार एवं मात्र 4.00 प्रतिशत नकारात्मक विचार प्रस्तुत करती हैं।

अतः इससे स्पष्ट है कि अब जनजातीय समाज में भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। जिसका लाभ भी जनजातियों को मिल रहा है। अब इनको भी शिक्षा के महत्व की जानकारी हो रही है। इसी कारण से ये लोग भी बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव-

गोंड जनजाति आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। विभिन्न शासकीय तथा कल्याणकारी-योजनाएं चलाये जाने के बाद भी जो परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। शोध निष्कर्ष से यह प्रदर्शित होता है कि चिकित्सा, शिक्षा तथा संस्कृति में परम्परागत स्थिति आज भी बनी हुई है। अभी भी शिक्षा के प्रति रुझान बहुत कम है तथा चिकित्सा में परम्परागत तरीका जैसे झाड़-फंक तथा देशी जड़ी-बूटियों पर निर्भर है। सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों को जनजातियों के विकास हेतु नयी योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने होंगे साथ ही पुरानी कल्याणकारी तथा विकास हेतु योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय जन प्रतिनिधियों तथा लोगों की योजनाएं लागू करने में सहभागिता

बढ़ानी होगी। विशेषकर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा क्योंकि जब उनका स्वास्थ्य तथा शिक्षा में विकास होगा तभी उनकी सोच बदलेगी तथा स्वयं के विकास हेतु जागरूक होंगे। महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षित करना होगा। चिकित्सा में आधुनिक औषधियों के प्रयोग हेतु जागरूक करना होगा जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक तौर पर भी उनको जागरूक करना होगा ताकि अपने सम्पूर्ण विकास हेतु स्वयं प्रयासरत हों।

संदर्भ

चौधरी, बी.डी. (1982) "ट्राइबल डेव्हलपमेंट इन इंडिया ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

डन्हा, ए.के. (1973) "ट्राइबल इकोनामी एन्ड देयर ट्रान्सफारमेशन ", नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल फार सोशल रिसर्च।

डिलीज राबर्ट (1985) "दि भील्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया ", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

देवगांवकर, एस.जी. "प्राब्लम्स ऑफ डेव्हलपमेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियास ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

देवगांवकर, एस.जी.(1990)"कोरकू ट्राइबल्स " कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली,

देवगांवकर, एस.जी.-"ट्राइबल्स डेवलपमेंट प्लान्स: इक्विमेंटेशन एण्ड इवैलुएशन ", कान्सेप्ट पब्लिशिंग कं., नई दिल्ली।

दुबे एस सी (1977) (संपादित) ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वाल्यूम 1. नई दिल्ली विकास।

एल्विन, वेरियर (1963) "ए. न्यू डील फार इंडिया ", नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।

फुक्स, एस. (1960) "दि गॉड एन्ड भूमिया ऑफ ईस्टर्न मंडला ", एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।

जैन, सी.के. एवं शर्मा एस.के. (1991)"ट्राइबल्स आफ मध्यप्रदेश: डैबिटेड एण्ड इकानामी " पृ.225-245,

पालीवाल, चन्द्र मोहन, (1986) "आदिवासी-हरिजन आर्थिक विकास: बस्तर जिले के संदर्भ में ", नार्दर्न बुक सेंटर, नई दिल्ली।

- पटेल, एम.एल. (1984) "ट्राइबल डेव्हलपमेंट ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- रायजादा, अजित (1984) "ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्यप्रदेश ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- शर्मा, ब्रम्हदेव, (1986) "आदिवासी विकास-एक सैद्धान्तिक विवेचन " तृतीय आवृत्ति, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
- शर्मा, एस.के. (1989) "रिसोसट डेवलपमेंट इन ट्राइबल इण्डिया ", नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।
- शर्मा, एस.के. (1993) "एक्सप्लवाइटेड आफ नेचुरल रिसोर्सेस इन ट्राइबल रीजन्स
- तिवारी, डी,एन. (1984) "प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ इंडिया ", गवर्नमेंट आफ मध्यप्रदेश मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, नई दिल्ली।
- तिवारी, शिवकुमार (1982) "मध्यप्रदेश के आदिवासी ", मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
- तिवारी शिवकुमार "सीनेरियो ऑफ दि इवैल्यूएशन एन्ड एक्सप्लाइटेड आफ ट्राइबल रिसोर्स " प्रकाशित कीनोट एड्रेस एट दि नेशनल कान्फ्रेंस, इन्दौर।
- तिवारी शिवकुमार (1992) "भारत की जनजातियां ", नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।
- शर्मा, ब्रह्मदेव, (1980) आदिवासी विकास: एक सैद्धान्तिक विवेचन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
- पूरे. जी.एस., (1963) 1963, द मिड्यूल्ड ट्राइब्स पापूलर प्रका-न, बम्बई
- Bairathi, Shashi(1991), *Tribal Culture Economy and Health*, Rawat Publication, Jaipur.
- Bardhan, A.B. (1973), *The tribal problem in India*, Deep and Deep Publication, New Delhi.
- Chaudhary , S. N.(2004), *Dalit and Tribal leadership in Panchayats* , Concept Publishing Company New Delhi.
- Dube,B.K. (1972) *Primitiv Tribes* in B. Kuppaswamy(ed.) *Social Change in India*,New Delhi.

- Gedam, Ratnakar (1995), *Poverty in India : Myth and Reality : Definition and Identification, Critical Evolution*, Deep & Deep Publication, New Delhi.
- Gorden, David M.(1998) , *Economics and Social Justice : Essays on Power, labour and Institutional Change* , Edward Elgar, Cheltenham.
- Gour, K.D.(1998), *Management of Poverty Alleviation in India*, Manak Publication, New Delhi.
- Kumar, Narendra (2006), *Dalit leadership in Panchayats*, Rawat Publication, Jaipur.
- Lieten,G. K. (1996), *Development, Devolution and Democracy Village Discourse in West Bengal*, Sage Publication, New Delhi.
- Londono, Juan luis (1996), *Poverty, Inequality and Human Capital Development in Latin America*, The World Bank , Washington D.C..
- Sachchidananda (2007), *Empowerment of Dalit Through Panchayati Raj : The Bihar Experience*, Serials Publication, New Delhi.
- Seetharamu, A.S. (1985), *Education in Rural Areas, Constraints and Prospects*, Ashish Publishing House, New Delhi – 110026
- Sharma, S. Ram (1995), *Education of Woman of Scheduled Castes and Scheduled Tribes*, Discovery Publishing House, New Delhi -110002.